HINDUSTAN TIMES, Delhi, 8.2.2022
Page No. 16, Size:(8.93)cms X (9.56)cms.

GAIL registers highest ever Revenue, PBT and PAT

GAIL (India) Limited has surpassed all parameters of financial performance in the third quarter of financial year 2021-22 on account of improved gas marketing spread, better product prices and improved operating efficiency in petrochemicals & liquid hydrocarbons. GAIL posted 20 per cent increase in Revenue from Operations to Rs 25,776 crore in Q3 FY22 as against Rs 21,515 crore in Q2 FY22, Profit before Tax (PBT) increased by 17% in Q3 FY22 to Rs 4,308 crore as against Rs 3,682 crore in Q2 FY22.

The Profit after Tax (PAT) increased by 15% to Rs 3,288 crore in Q3 FY22 as against Rs 2,863 crore in Q2 FY22. Revenue from operations for 9 month period ended on December 31, 2021 increased by 57% to Rs 64,678 crore as compared to Rs 41,189 crore in corresponding period of previous year. PBT registered a growth of 166 per cent & stood at Rs 10,044 crore upto Q3 FY22 as against Rs 3,774 crore upto Q3 FY21. PAT increased by 158% to Rs 7,681 crore upto Q3 FY22 as against Rs 2,983 crore upto Q3 FY21 mainly on account of improved gas marketing spread, better product prices, better physical performance in Gas Marketing and Transmission segment.

On a Consolidated basis, Revenue from Operations increased by 20% in Q3 FY22 to Rs 26,176 crore v/s Rs 21,782 crore in Q2 FY22. The PBT in Q3 FY22 was up by 29% to Rs 4,820 crore v/s Rs 3,728 crore in Q2 FY22 & PAT in Q3 FY22 increased by 31% to Rs 3,781 crore v/s Rs 2,883 crore in Q2 FY22.

INDIAN EXPRESS, Delhi, 8.2.2022
Page No. 4, Size:(7.67)cms X (23.20)cms.

Begin demolition of Supertech twin towers in 2 weeks, SC tells authorities

On August 31, 2021, the SC had upheld an Allahabad HC ruling asking the builder group to demolish the twin towers

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, FEBRUARY 7

THE SUPREME Court Monday directed that the demolition of the 40-storey twin towers built by real-estate major Supertech Ltd in violation of norms at its Emerald Court project in Noida (New Okhla Industrial Development Authority) start within two weeks.

"The CEO Noida shall take all necessary steps for observing directions of this court. Work of demolition shall commence no later than two weeks from this order," a bench of Justices D Y Chandrachud and Surya Kant said and asked the CEO to convene a meeting with all agencies concerned with the demolition including the Gas Authority of India Ltd (GAIL) within 72 hours so as to finalise the dates and schedule for it.

Supertech's counsel informed the court during the hearing that an email was received from the Noida authority on February 5 intimating that necessary clearances for the demolition have been received. The counsel also told the court a cheque for the amount of Rs 70 lakh has been forwarded to the agency earmarked for carrying out the work.

"The CEO Noida shall take all necessary steps for observing the directions of this court and the work of demolition shall commence no later than within a period of two weeks from the date of this order", the bench directed.

On August 31, 2021, the SC had upheld an Allahabad High Court ruling asking the builder group to demolish the twin towers, and sanctioning prosecution of the officials. The SC found the towers flouted regulations regarding distance to be maintained between buildings, fire safety regulations and were constructed "through acts of collusion between officers of NOIDA... and the" group. It also gave the go-ahead for prosecuting officials of both for violation of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 and Uttar Pradesh Apartments Act, 2010.

The SC pointed out that the purpose of the regulations is to ensure the protection of the environment and well-being and safety of those who occupy these constructions and "when these regulations are brazenly violated by developers, more often than not with the connivance of regulatory authorities, it strikes at the very core of urban planning, thereby directly resulting in an increased harm to the environment and a dilution of safety standards". Therefore, it added, "illegal construction has to be dealt with strictly to ensure compliance with the rule of law".

Subsequently, on January 12, the top court pulled up the group for not complying with its order to demolish the towers and warned its directors that they will be sent to jail for "playing truant with the court". On February 4, it also directed that refunds, as computed by the Amicus Curiae, shall be paid to home buyers on or before February 28.

AMAR UJALA, Delhi, 8.2.2022
Page No. 10, Size:(20.40)cms X (13.96)cms.

कोई भी प्राधिकरण नहीं कर सकता एनओसी से इनकार : सुप्रीम कोर्ट

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सुपरटेक की ओर से पेश वकील ने कहा कि ट्विन टावर से करीब पांच मीटर की दूरी पर गैस पाइपलाइन है, जिसमें बहुत अधिक प्रेशर हैं।

ढहाने के दौरान पाइप लाइन को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए गेल इंडिया से एनओसी की दरकार है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी भी प्राधिकरण द्वारा एनओसी देने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया है। नोएडा प्राधिकरण के वकील ने पीठ को बताया कि ढहाने के काम के वक्त यातायात समेत अन्य चीजों को लेकर यातायात पुलिस सहित गौतमबुद्ध नगर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है।

गैस लाइन के लिए गेल से चाहिए दस्तावेज

सुपरटेक ट्विन टावर मामला

एटीएस सोसाइटी के तर्क पर विचार से इनकार

सुनवाई के दौरान ट्विन टावर के पास स्थित एटीएस सोसायटी की ओर से पेश वकील ने पीठ से कहा कि ढहाने की कार्रवाई के दौरान उसके हितों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन पीठ ने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया।

हाईकोर्ट के आदेश को रखा था बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें भवन मानदंडों के उल्लंघन के लिए सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 मंजिला ट्विन टावर-16(अपेक्स) और 17 (स्यान) को ढहाने का आदेश दिया गया था। सुपरटेक को तीन महीने के भीतर टावरों को गिराने का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया था। ढहाने का कार्य नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की देखरेख में होने की बात कही गई थी। सुपरटेक को इस मद पर होने वाले खर्च का वहन करने के लिए कहा गया था। साथ ही कोर्ट ने सुपरटेक को दो महीने के भीतर ट्विन टावरों के फ्लैट खरीदारों को 12 फीसदी प्रति वर्ष ब्याज के साथ राशि वापस करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने बिल्डर को एक महीने के भीतर एमराल्ड कोर्ट ओनर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को हर्जाने के तौर पर दो करोड़ रुपये का भुगतान करने को भी कहा था।

...फिर शुरू होगा ट्विन टावर ढहाने का काउंट डाउन

नोएडा। सुप्रीम कोर्ट के सोमवार के आदेश के बाद ट्विन टावर ध्वस्तीकरण की स्थिति अब पूरी तरह से साफ होने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दो सप्ताह में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करनी होगी। उधर, आदेश से पहले ही प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रितु माहेश्वरी ने इस मामले में बुधवार को सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है। सुपरटेक ने भी इमारत ध्वस्त करने वाली मुंबई की कंपनी एडिफिस को 70 लाख रुपये का चेक एडवांस पेमेंट के रूप में दिया है। कंपनी का कहना है कि मंगलवार तक चेक क्लियर होने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा।

माहेश्वरी ने बताया कि ट्विन टावर को ध्वस्त करने से पूर्व उन्होंने संबंधित सभी विभागों की बुधवार दोपहर 12 बजे बैठक बुलाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सोमवार को आदेश में यह कहा है कि 72 घंटे के अंदर सीईओ की अध्यक्षता में बैठक होनी चाहिए, हालांकि हम इससे पहले ही बैठक की तारीख फाइनल कर चुके हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2 सप्ताह में ट्विन टावर विध्वंस किया जाना है, यह गलत है। सुपरटेक ने 6 महीने की अदालती वार्ता में कार्ययोजना प्रस्तुत की है। जिसमें साढ़े 3 महीने विध्वंस का समय है। ब्यूरो